दैनिक

फाईट अगेंस्ट क्रिमिनल

वर्ष : ०९ | अंक:८६ | मुंबई, गुरूवार ०७ अगस्त २०२५ | RNI. No. : MAHHIN/2016/71734 | पृष्ठ-४ | मूल्य २/रू.

6.41 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के चूर्ण और हाइड्रोपोनिक खरपतवार की तस्करी; हवाई अड्डे के कर्मचारी सहित दो व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई : सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुल 6.41 करोड़ रुपये

मूल्य के सोने के चूर्ण और हाइड्रोपोनिक खरपतवार की तस्करी के दो अलग-अलग प्रयासों के सिलसिले में एक हवाई अड्डे के कर्मचारी सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार, ये बरामदगी 3 और 4 अगस्त, 2025 को नियमित ड्यूटी के दौरान मुंबई सीमा शुल्क के हवाई अड्डा आयुक्तालय द्वारा की गई थी।

पहला मामला एक पारगमन यात्री से जुड़ा था जिसने कथित तौर पर एक हवाई अड्डे के कर्मचारी को 1.51 किलोग्राम (1,510 ग्राम) मोम में लिपटा सोने का चूर्ण, जिसकी कीमत 1.39 करोड़ रुपये है, सौंपा था। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी ने बाद में यात्री से 24 कैरेट सोने के चूर्ण के चार पैकेट लेने की बात स्वीकार की। 3/4 अगस्त 2025 को ड्यूटी के दौरान, मुंबई सीमा शुल्क (हवाई अड्डा आयुक्तालय) ने सीएसएमआई हवाई अड्डे पर ₹6.41 करोड़ मूल्य का प्रतिबंधित सामान जब्त किया। दो अलग-अलग मामलों में, अधिकारियों ने बैंकॉक से लौटे एक यात्री से 5.027 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक खरपतवार और 1.51 किलोग्राम सोने की धूल बरामद की।

गोवा से लाई जा रही 13 लाख रुपये की विदेशी शराब ज़ब्त

पनवेल : महाराष्ट्र आबकारी विभाग के उड़न दस्ते ने महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले के पनवेल इलाके में गोवा से लाई जा रही 13 लाख रुपये की विदेशी शराब ज़ब्त की । आबकारी विभाग के अनुसार , यह शराब आठ अलग-

अलग विदेशी ब्रांडों की थी, जिन्हें स्पेयर पार्ट्स की आड़ में तस्करी करके लाया जा रहा था। आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त प्रसाद सुर्वे ने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'अधिकारियों ने राजस्थान निवासी उत्तम सेन और भयंदर के रमेश पुरोहित को मौके से गिरफ्तार किया है। उनके पास से तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिनसे तस्करी रैकेट में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दोनों आरोपियों को पनवेल कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच में पता चला है कि यह किसी अंतरराज्यीय गिरोह का काम हो सकता है।' रविवार को, मादक पदार्थों की तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई में, मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र-3 के हवाई अड्डा आयुक्तालय के अधिकारियों ने अभियान के दौरान लगभग 14.73 करोड़ रुपये मूल्य की 14.738 किलोग्राम संदिग्ध एनडीपीएस हाइड्रोपोनिक खरपतवार (मारिजुआना) जब्त की। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि ये बरामदगी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई) पर की गई, जिसके परिणामस्वरूप एक यात्री को गिरफ्तार किया गया। यात्री को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, 'विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई), मुंबई के सीमा शुल्क अधिकारियों ने उड़ान संख्या एमएच 194 से बैंकॉक से आ रहे एक यात्री को रोका।' एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इससे पहले 29 और 30 जुलाई के बीच चलाए गए अभियान के दौरान, मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र-3 के हवाई अड्डा आयुक्तालय के अधिकारियों ने लगभग 8 करोड़ रुपये मूल्य का 8.012 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक खरपतवार (मारिजुआना) जब्त किया था।

कबूतर जा... जा... जा...

दाना बंद, आस्था बंद? कबूतरखाने पर कोर्ट की सख्ती से जैन समाज में उबाल

मनसे के अविनाश जाधव ने कहा कि एक माधुरी के लिए वनतारा बना सकते हैं तो कबूतरों के लिए क्या? जैन समाज एकदम शांतिप्रिय समाज है और अचानक इस तरह का हल्ला करना यह भी एक चौकानोली बात है

कबूरतरखाने के लिए विरोध करे लोगों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में एडवोकेट पुर्णिमा मेहता ने कहा कि यह तो सदियों से चलता आ रहा है और अचानक आए इस फैसले पर सरकार को खुद आगे चलकर इस फैसले पर विचार विमर्श करना चाहिए

सईद शेख

मुंबई। दादर के कबूतरखाने में अब ना गुटरगूं की गूंज है, ना ही आस्था का उन्मुक्त उछाल। तिरपाल के नीचे दब चुकी है वो परंपरा, जो कई समुदायों के लिए वर्षों से 'पुण्य' का प्रतीक रही है। मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने हाई कोर्ट के निर्देश पर कबूतरों को दाना डालने पर बैन लगाकर कबूतरखाने को तिरपाल से ढंक दिया है। इसका मकसद है - फेफड़ों की बीमारी से जनता को बचाना। मगर इससे छिड़ गया है एक भावनात्मक और धार्मिक बहस, जो अब सड़कों से लेकर मंत्रियों के पत्रों तक जा पहुंची है। कबूतर, जो कभी प्रेम का प्रतीक रहे, संदेशवाहक माने गए, और फिल्मों में इश्क़ के दूत बने, अब मुंबई में 'स्वास्थ्य संकट' के आरोपी हैं। अदालत ने साफ शब्दों में कहा - सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना डालना एक उपद्रव है और इससे लोगों की सेहत पर असर पड़ता है। बीएमसी को निर्देश मिला - कार्रवाई करो, एफआईआर दर्ज करो। माहिम में पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है, जो कार से एल.जे. रोड पर कबूतरों को दाना डालता देखा गया। यह इस आदेश के तहत दर्ज हुई मुंबई की पहली एफआईआर है। इससे पहले BMC ने दादर कबूतरखाना को तिरपाल से ढककर साफ संदेश दे दिया - 'अब दाना नहीं'। मगर इस फैसले ने धार्मिक आस्थाओं में खलबली मचा दी है। विशेष तौर पर जैन समुदाय, जिसके लिए जीवदया (जीवों पर करुणा) धर्म का मूल है। दादर का कबूतरखाना भी जैन मंदिर की देखरेख में है और यही कारण है कि प्रतिबंध को समुदाय अपने धर्म के अधिकारों पर सीधी चोट मान रहा है।

राज्य के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने BMC आयुक्त को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे - इसके लिए 'सौहार्दपूर्ण समाधान' निकाला जाए। यानी आस्था भी बचे और स्वास्थ्य का ध्यान भी। मुंबई की गलियों में कबूतरों को दाना डालना वर्षों से पुण्य का कार्य माना जाता रहा है। अमावस्या पर तो यह विशेष धार्मिक महत्व रखता है - पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति से लेकर आशीर्वाद की कामना तक जुड़ी है यह परंपरा। मगर विशेषज्ञों की मानें, तो कबूतर की बीट से क्रिप्टोकोकोसिस या हाइपरसेंसिटिविटी पन्यूमोनाइटिस जैसे फेफड़ों के रोग हो सकते हैं, खासकर उन लोगों में जो लंबे समय तक उनके संपर्क में रहते हैं। अब सवाल यह है - क्या सेहत की दुहाई आस्था पर भारी पड़ेगी? या क्या दोनों के बीच कोई संतुलन निकलेगा? मुंबई जैसे शहर में जहां हर गली, हर चौक में परंपरा की परतें बिछी हैं, वहां एक कबूतरखाने का तिरपाल, महज प्लास्टिक नहीं, एक बड़ी बहस का प्रतीक बन चुका है - सेहत बनाम श्रद्धा।

किसानों के कर्जमाफी को लेकर पूर्व विधायक बच्चू कडू की राज ठाकरे से मुलाकात

प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बच्चू कडू बुधवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात के लिए उनके निवास पहुंचे. इस मुलाकात को किसानों की आत्महत्या और दिव्यांगों के अधिकार जैसे अहम सामाजिक मुद्दों के मद्देनज़र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मनसे नेता बाला नांदगांवकर ने पीटीआई से बातचीत में बताया कि, 'बच्चू कडू आज राज साहब से मिलने आए थे. उन्होंने साहब के साथ दो मुख्य मुद्दों पर चर्चा की, एक किसानों के बारे में और दूसरा दिव्यांगों को लेकर. बच्चू कडू पहले से ही किसानों की कर्जमाफी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और हमारी पार्टी ने भी उस लड़ाई में उन्हें पूरा समर्थन दिया है.' इस बातचीत में दोनों नेताओं ने किसानों की आत्महत्या के गंभीर विषय पर गहन विचार-विमर्श किया. बच्चू कडू ने बताया कि राज्य में शायद ही कोई दिन ऐसा जाता है जब किसी किसान ने आत्महत्या न की हो. उन्होंने कहा, 'हमारी कोशिश है कि हम सभी दलों के नेताओं से मिलें और इस मुद्दे को एक सशक्त आंदोलन का रूप दें. हमें उम्मीद है कि अन्य पार्टियों से भी समर्थन मिलेगा और हम इस सामाजिक त्रासदी के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएंगे.' बच्चू कडू के मुताबिक, किसानों की आर्थिक स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है, और इस पर केवल राजनीतिक बयानबाज़ी से काम नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि प्रहार संगठन अब इस मुद्दे को लेकर सभी विपक्षी और सत्ताधारी दलों से संवाद करेगा, ताकि कोई ठोस नीति बनाई जा सके. दूसरी ओर, दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर भी चर्चा हुई जिसमें दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि सरकार की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करने में कई खामियां हैं. इस विषय पर भी आने वाले समय में एक संयुक्त मोर्चा तैयार करने की बात कही गई. इस मुलाकात को राजनीतिक हलकों में काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि बच्चू कडू और राज ठाकरे दोनों ही राज्य में अपने बेबाक और स्पष्ट बयानों के लिए जाने जाते हैं. अब देखना होगा कि यह मुलाकात भविष्य में कोई साझा आंदोलन की रूपरेखा तय करती है या नहीं.

अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले पर राहुल गांधी को कोर्ट से मिली जमानत

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा की एक एमपी-एमएलए अदालत ने 2018 में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े एक मामले में बुधवार को जमानत दे दी। जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी सुबह करीब 10.55 बजे अदालत में पेश हुए। इस दौरान कांग्रेस सांसद के वकील ने कहा, 'राहुल गांधी झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अदालत में पेश हुए। उन्होंने जमानत मांगी थी, जो मंजूर हो गई। अब हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।' बता दें कि राहुल गांधी मंगलवार को झारखंड पहुंचे थे। वे यहां पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे, जो रामगढ़ जिले के उनके पैतृक गांव नेमरा में हुआ। यह मामला 2018 में चाईबासा में एक चुनावी रैली के दौरान दिए गए भाषण से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी को लेकर प्रताप कुमार नाम के एक शख्स ने चाईबासा के मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। प्रताप कुमार का आरोप है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यह बयान दिया था। इससे पहले राहुल गांधी ने 2 जून को झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया था और विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें 26 जून को पेश होने का निर्देश दिया गया था। कांग्रेस सांसद के वकील ने 10 जून को उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि उनके मुवक्किल निर्धारित दिन पर पेश नहीं हो पाएंगे, और इसके बजाय उन्होंने 6 अगस्त की तारीख देने का अनुरोध किया था।उच्च न्यायालय ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया था। इस बीच, राहुल गांधी के आगमन से पहले पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबास में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उप-मंडल अधिकारी (सदर) संदीप अनुराग टोपनो ने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। अधिकारियों के अनुसार, राहुल गांधी रांची से चाईबासा पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर से गए। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिए टाटा कॉलेज ग्राउंड में एक हेलीपैड बनाया गया था।

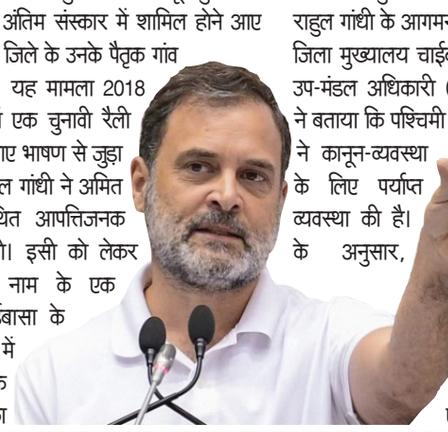

SHABBIR MEMON (DIRECTOR) 9892488825. TEL: 022 6780894

MEMON REALTORS

Builder & Devloper PVT. LTD.

Shop No. 1 to 5, Bldg,. No . 2 Next Ahuja Bulding R.M. Road, Oshiwara, Jogeshwari(W), Mumbai - 400 102. memonshabbir24@gmail.com

अचानक लिया गया यह फैसला किसी के दबाव में था या अपने बचाव में !

अडानी पोर्ट्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा

नरेंद्र मोदी के साथ उभरे गौतम अडानी पर शिकंजा कसता जा रहा है। जी हाँ, गौतम अडानी। मोदी के अजेय अरबपति दोस्त ने उनके सबसे लाभदायक व्यवसाय, अडानी पोर्ट्स के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो, देश के 28% ट्रैफ़िक वाले सबसे बड़े बंदरगाह संचालक, अडानी पोर्ट के कप्तान को जहाज छोड़ने के लिए किस बात ने मजबूर किया? आइए, इन बिंदुओं को जोड़ते हैं। अडानी पोर्ट्स जांच के घेरे में है, और इसकी आंच सीधे अमेरिका से आ रही है। दरअसल, अमेरिकी अधिकारी इस बात की जाँच कर रहे हैं कि क्या अडानी ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए मुंद्रा पोर्ट के ज़रिए ईरानी रसोई गैस का अवैध आयात किया था। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा उजागर किए

गए 25 करोड़ डॉलर के रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले की अब अमेरिकी अभियोजकों और एसईसी द्वारा जाँच की जा रही है। ऐसे आरोप हैं कि अडानी ने अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया और भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी, और यह तूफ़ान अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। वैश्विक स्तर पर इसका असर तेज़ी से सामने आ रहा है। केन्या ने 2.6 अरब डॉलर के अडानी के दो बुनियादी ढाँचे के सौदों को रद्द कर दिया है। श्रीलंका ने एक बिजली समझौते से हाथ खींच लिया है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और ईरान जाँच शुरू कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। अमेरिका स्थित संस्थागत निवेशक भी अडानी समूह में अपने निवेश का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह हैः क्या मोदी के जिगरी दोस्त अडानी को कभी भारत में जवाबदेह ठहराया जाएगा? जवाब है नहीं, और हम जानते हैं क्योंः क्योंकि अगर अडानी गिरते हैं, तो मोदी भी गिरेंगे।

संपादकीय

एम.एस.शेख
संपादक

देश में हरित क्रांति के जनक वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथ

वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथ का पूरा नाम मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथ था। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। वह कृषि वैज्ञानिक के साथ ही पादप आनुवंशिकीविद (ईंत्हू उाहूग्म्) भी थे। उनको 1972 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (घ्ण्) का महानिदेशक बनाया गया और भारत सरकार के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। देश में हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन (शए ैंस्र्हूीप्) को केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया गया वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथ ने देश को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा काम किया था। स्वामीनाथन ने गेहूं और चावल की ऐसी वेरायटी तैयार की थी जिससे न केवल पैदावार में इजाफा हुआ, बल्कि उनके प्रयासों से देश को सूखे से बचाने में भी मदद मिली। उनका विवाह मीना स्वामीनाथन से हुआ था, जिनसे उनकी मुलाकात 1951 में हुई थी जब वे दोनों कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे। वे चेन्नई, तमिलनाडु में रहते थे। उनकी तीन बेटियाँ सौम्या स्वामीनाथन (एक बाल रोग विशेषज्ञ), मधुरा स्वामीनाथन (एक अर्थशास्त्री), और नित्या स्वामीनाथन (लिंग और ग्रामीण विकास) हैं।गांधी और रमण महर्षि ने उनके जीवन को प्रभावित किया।अपने परिवार के स्वामित्व वाली 2000 एकड़ जमीन में से, उन्होंने एक तिहाई विनोबा भावे के कारण दान कर दी। 1960 के दशक में भारत समेत पड़ोसी देशों को अकाल की स्थिति से बचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था।बाद में 1979 में वह प्रधान सचिव बनाए गए थे। वह योजना आयोग में भी रहे। देश को सूखे से बचाने पर उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था।अपने करियर की शुरुआत सिविल सेवा से की, लेकिन उनकी रुचि कृषि में थी। इस वजह से उन्होंने इस क्षेत्र में रिसर्च करना शुरू कर दिया। यूरोप और अमेरिका के कई बड़े संस्थानों में उन्होंने अपने रिसर्च से महत्वपूर्ण खोजे कीं और उपलब्धियां हासिल कीं। 1954 में उन्होंने सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट (Central Rice Research Institute) कटक में जैपोनिका किस्मों से इंडिका किस्मों में फर्टिलाइजर रिस्पांस के लिए जीन ट्रांसफार्मर करने पर बड़ा काम किया।उन्होंने इसे ‘उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने का पहला प्रयास बताया जो अच्छी मिट्टी की उर्वरता और अच्छे जल प्रबंधन का जवाब दे सकती हैं।’इसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि आज़ादी के बाद भारतीय कृषि बहुत अधिक उत्पादक नहीं थी। वर्षों के औपनिवेशिक शासन ने इसके विकास को प्रभावित किया और देश के पास इस क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए संसाधनों की कमी थी।

सड़कें अतिक्रमण से छुड़ाई, सियासत बौखलाईः और अब आयुक्त शर्मा के तबादले की आहट?

अब आयुक्त से स्वच्छता पर भी ‘एक्शन रिप्ले’ की उम्मीद

अमरावती। बडनेरा की सड़कों पर बुधवार को एक अलग ही तस्वीर दिखी - एक्शन में नगर निगम, साथ में पुलिस दस्ता और नेतृत्व में सख्त मिज़ाज की नगर आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की इस मुहिम ने अब बडनेरा की ओर रुख कर लिया है, जहां जयहिंद चौक, चांदनी चौक और जुनी बस्ती के रास्तों को अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त किया गया। जब से आयुक्त शर्मा ने पदभार संभाला है, अमरावती-बडनेरा के रास्तों से अनधिकृत कब्जे हटाने की मुहिम ने तेज़ी पकड़ी है। बुधवार 6 अगस्त को मनपा का दस्ता पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा। कंटिन्यू निगरानी दल, पुलिस प्रशासन और अतिक्रमण विरोधी स्क्वॉड ने मिलकर सड़क के दोनों ओर लगे ठेले, फलगाड़ियां, और दुकानों के आगे बढ़ाए गए अवैध शेड, छपरी सब हटाए। मनपा ने आठ दिन पहले जिन दुकानदारों को नोटिस थमाए थे, उन्हें बुधवार को हकीकत का सामना करना पड़ा। जिन दुकानों के बाहर दो-तीन फुट का शेड या तिरपाल निकाला गया था, उन्हें भी हटाया गया। यही नहीं, उन क्षेत्रों में भी कार्रवाई की गई जहां अक्सर राजनीतिक पहुंच के कारण अतिक्रमण बना रहता था। बडनेरा शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शुमार जयहिंद चौक का परिसर, चांदनी चौक से जुड़ी गलियां और जुनी बस्ती के तंग रास्ते अब पहली बार खुलकर सांस ले रहे हैं। यहां की जनता ने राहत की सांस ली है, क्योंकि लंबे समय से ये इलाके जाम और अव्यवस्था से त्रस्त थे। इसी बीच कुछ स्थानीय नेताओं और संगठनों ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ये कार्रवाई केवल गरीबों पर हो रही है, ‘बड़े’ अतिक्रमण untouched हैं। वहीं, सूत्रों की मानें तो कुछ राजनीतिक चेहरों की ‘सुनवाई’ न करने के कारण आयुक्त शर्मा के तबादले की भी चर्चाएं चल रही हैं। सवाल उठता है - जब एक अधिकारी बिना भेदभाव कानून का पालन कर रहा है, शहर की भीड़ और अराजकता को नियंत्रित कर रहा है, तो फिर उसे निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? नगर आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक की यह कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कवायद नहीं, बल्कि अमरावती को व्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम बनाने का अभियान है। इस पर सियासत करना शहर के साथ अन्याय होगा।

अब नागरिकों की नई मांग - स्वच्छता पर भी चले ‘सख्त बुलडोज़र’

शहर के जागरूक नागरिकों का कहना है कि जैसे आयुक्त ने अतिक्रमण पर स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है, वैसे ही अब उन्हें शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर भी मोर्चा खोलना चाहिए। जगह-जगह जमा कचरा, नालियों की सफाई, और कचरा प्रबंधन की कमजोरियां अब अगला बड़ा मुद्दा बनती जा रही हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अतिक्रमण की तरह गंदगी पर भी नगर प्रशासन ‘बिना समझौते’ के कदम उठाएगा।

तमन्ना भाटिया का ब्यूटी ट्रीटमेंट पर बयानः कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट अब आम

बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को अक्सर उनके खूबसूरत चेहरे और बेदाग त्वचा के चलते ‘मिल्की ब्यूटी’ कहा जाता है। हालांकि, उनकी गोरी रंगत को लेकर कई बार सवाल भी उठाए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि तमन्ना ब्यूटी ट्रीटमेंट या कॉस्मेटिक प्रोसीजर का सहारा लेती हैं। इंडस्ट्री में इस तरह के ट्रीटमेंट को लेकर सेलेब्स अक्सर ट्रोलिंग का शिकार होते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की अचानक मौत के बाद यह मुद्दा और भी सुर्खियों में आ गया। इस बीच, तमन्ना भाटिया ने इस संवेदनशील विषय पर खुलकर अपनी राय रखी है।

हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में तमन्ना ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना आसान है क्योंकि लोग सेलेब्स की ज़िंदगी को सार्वजनिक मानते हैं। उन्होंने कहा, ‘मीडिया की नजरों में रहने वाले लोगों के बारे में बात करना बहुत आसान होता है। क्योंकि आप उनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते और जान भी नहीं पाएंगे। इन मुद्दों पर चर्चा करने से हम कहीं नहीं पहुंचते।’ तमन्ना ने आगे बताया कि अब बोटोक्स और स्किन ट्रीटमेंट जैसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर को टैबू नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी सेलेब्स इस पर खुलकर बात करने से बचते हैं। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी यानी जेन-जी इन बातों को लेकर अधिक सहज है। ‘जो भी ऐसा ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो इस पर खुलकर बात करते हैं। लेकिन कई लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वो जज नहीं होना चाहते। फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों पर पहले ही काफी उंगलियां उठती हैं, इसलिए वे अपनी निजी जिंदगी शेयर करने में सहज नहीं होते।’ तमन्ना का यह बयान इंडस्ट्री में सौंदर्य मानकों और उन पर लगे सामाजिक दबाव को उजागर करता है। उनका कहना है कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट अब आम हो चुके हैं और हर व्यक्ति को अपनी पसंद से फैसले लेने का अधिकार है, बशर्ते उस पर जजमेंट न किया जाए।

शुभमन सहित तीन खिलाड़ी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की दौड़ में शामिल

भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल सहित तीन खिलाड़ियों को जुलाई माह के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामांकित किया गया हैं। इस पुरस्कार की दौड़ में शुभमन के अलावा इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर भी शामिल हैं। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 75.40 की औसत के साथ 754 रन बनाए। बर्मिंघम में खेले गए मैच में उन्होंने 269 और 161 रन की पारी खेली थी। शुभमन गिल ने इस टेस्ट सीरीज 147, 8, 269, 161, 16, 6, 12, 103, 21 और 11 रन की पारी खेली।

वहीं कप्तान के रूप में अपनी पहली सीरीज खेलते हुए शुभमन ने जबरदस्त खेल दिखाया। उनकी कप्तानी में भारत ने पांच मुकाबलों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म की। वहीं, स्टोक्स ने चार मुकाबलों की सात पारियों में 43.43 की औसत के साथ 304 रन बनाए। इसमें शतकीय पारी भी शामिल है। इसके साथ ही स्टोक्स ने पूरी सीरीज में 17 विकेट भी हासिल किए। बेन स्टोक्स ने लगातार दो मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। लॉर्ड्स में उनके ऑलराउंड प्रदर्शन ने इंग्लैंड को 22 रनों से रोमांचक जीत दिलाई। वहीं मुल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दो टेस्ट मैचों में 265.5 की औसत से 531 रन बनाए। उन्होंने पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में 147 रनों की संयमित पारी खेली। मुल्डर ने बुलावायो में अपने करियर की सबसे बड़ी नाबाद 367 रनों की पारी खेली। यह दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट इतिहास में किसी बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। मुल्डर ने गेंदबाजी में भी 15.28 की औसत से सात विकेट लिए।

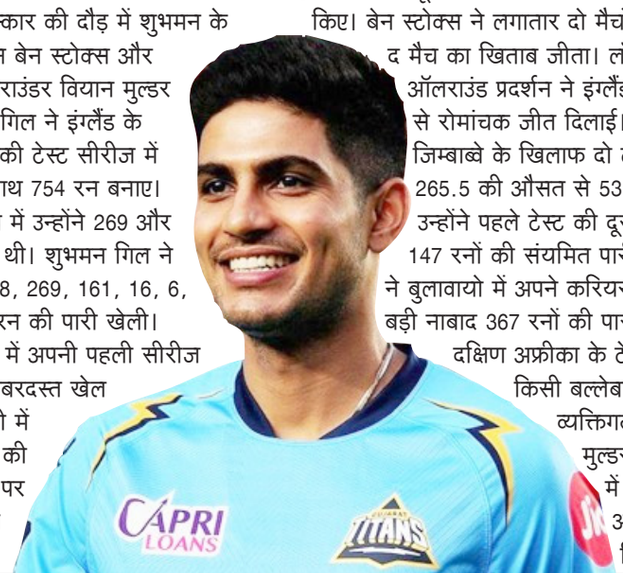

बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता अब बॉम्बे हाई कोर्ट की जज

न्याय की बेंच पर सियासत की परछाई?

मुंबई । बॉम्बे हाई कोर्ट की एक नई नियुक्ति पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से

एडवोकेट आरती अरुण साठे की बतौर न्यायाधीश सिफारिश के बाद विपक्ष ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवालों की बौछार कर दी है। वजह? आरती साठे महाराष्ट्र बीजेपी की आधिकारिक प्रवक्ता रह चुकी हैं। कॉलेजियम ने 28 जुलाई को उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी, लेकिन जैसे ही यह खबर सार्वजनिक हुई, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया। जब कोई व्यक्ति सत्ता पक्ष का सार्वजनिक चेहरा रह चुका हो, तो क्या उसकी न्यायिक भूमिका निष्पक्ष हो सकती है? 'यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि राजनीतिक संरक्षण का विस्तार है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की नींव हिला दी गई है।' आरती साठे का जवाब - 'मैं पहले ही पार्टी छोड़ चुकी हूं' विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए आरती साठे ने कहा कि उन्होंने पिछले साल ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और अब किसी भी राजनीतिक पार्टी से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने अपनी पेशेवर योग्यता और कानूनी अनुभव को इस नियुक्ति का आधार बताया। मामला सिर्फ एक नाम की नियुक्ति का नहीं, बल्कि न्यायपालिका की आत्मा की स्वतंत्रता का है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति, जो कभी सार्वजनिक रूप से सत्ताधारी दल की विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर चुका हो, अब न्याय के तराजू पर सबके लिए समान भाव रख पाएगा?

कई संवैधानिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मामलों में 'हितों के टकराव' की आशंका स्वाभाविक है। इससे न सिर्फ न्याय की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं, बल्कि अदालत की छवि भी दांव पर लगती है। आरती साठे की नियुक्ति ने एक गहरी बहस को जन्म दिया है - क्या न्यायिक व्यवस्था में भी अब सियासी समीकरण असर डालने लगे हैं। विपक्ष का कहना है कि यह महज एक नाम नहीं, एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत है, जहां लोकतंत्र की सबसे पवित्र संस्था - न्यायपालिका - को भी राजनीतिक रंग में रंगा जा रहा है।

फिलहाल, एक जज की नियुक्ति ने सवालों का पिटारा खोल दिया है। जवाब शायद वक्त देगा, लेकिन न्याय और राजनीति के बीच खिंचती इस रेखा को देश देख ज़रूर रहा है।

एनसीपी एस पी के रोहित पवार ने कहा कि भाजपा के नेता प्रवक्ता इसी तरह से न्यायालय की कुर्सी पर बैठेंगे तो किस तरह से न्याय मिल सकता है। जनता को न्याय मिलेगा इसकी उम्मीद जनता कैसे लगा सकती है।

शाम 4 बजे, गुजरात राज्य हज समिति के अध्यक्ष इकबालभाई सैयद और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू साहब ने नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर अचानक दौरा किया।

भारत रत्न ए.पी.जे. अब्दुल कलाम पुरस्कार। गुजरात राज्य हज समिति के अध्यक्ष के अच्छे कार्यों के लिए अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड द्वारा दिल्ली के रेस्ट क्लब में सम्मानित किया गया।

मुंबई के लिए 238 एसी लोकल ट्रेनों की खरीद को मंज़ूरी

मुंबई : दो साल की देरी के बाद, भारतीय रेलवे ने मुंबई के लिए 238 वातानुकूलित (एसी) लोकल ट्रेनों की खरीद को मंज़ूरी दे दी है,

जिसका उद्देश्य शहर में यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना है। रेलवे बोर्ड के सीईओ सतीश कुमार ने यह घोषणा की। उन्होंने पुष्टि की कि मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी-3 और एमयूटीपी-3ए) के तहत जल्द ही निविदाएँ जारी की जाएँगी। मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, इस खरीद की कुल अनुमानित लागत 19,293 करोड़ रुपये है।

एमयूटीपी-3 परियोजना में 3,491 करोड़ रुपये की लागत से 47 एसी लोकल ट्रेनों का अधिग्रहण शामिल है। दूसरी ओर, एमयूटीपी-3ए परियोजना 15,802 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ 191 एसी ट्रेनों की खरीद पर केंद्रित होगी। शुरुआत में, इन परियोजनाओं के लिए वैश्विक निविदाएँ मुंबई रेल विकास निगम (एमआरवीसी) द्वारा जून 2023 में जारी की गई थीं, लेकिन आगे बढ़ने के निर्णय में देरी हुई, जिससे खरीद की समयसीमा पीछे हो गई।

सीएनबीसी-टीवी18 के अनुसार, इस विकास को मुंबई में बेहतर स्थानीय यात्रा विकल्पों की बढ़ती माँग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वर्तमान में, मुंबई का उपनगरीय नेटवर्क मध्य और पश्चिमी रेलवे लाइनों पर प्रतिदिन 189 वातानुकूलित लोकल ट्रेन सेवाएँ चलाता है, जो 2,00,000 से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करती हैं।

नई ट्रेनों के शुरू होने से भीड़भाड़ कम होगी और आराम बढ़ेगा, और अधिक यात्रियों को समायोजित करने के लिए मौजूदा 12-डिब्बों वाली ट्रेनों को 15-डिब्बों वाली इकाइयों तक विस्तारित करने की योजना है। इन उन्नयनों के अलावा, रेलवे बोर्ड स्वचालित दरवाज़ा बंद करने वाली प्रणालियों वाली गैर-एसी ट्रेनों के दो प्रोटोटाइप पर भी काम कर रहा है, जिनके दिसंबर 2025 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। इन ट्रेनों का विकास चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फ़ैक्टरी में किया जा रहा है।

गोवा से लाई जा रही 13 लाख रुपये की विदेशी शराब ज़ब्त

पनवेल : महाराष्ट्र आबकारी विभाग के उड़न दस्ते ने महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले के पनवेल इलाके में गोवा से लाई जा रही 13 लाख रुपये की विदेशी शराब ज़ब्त की । आबकारी विभाग के अनुसार , यह शराब आठ अलग-अलग विदेशी ब्रांडों की थी, जिन्हें स्पेयर पार्ट्स की आड़ में तस्करी करके लाया जा रहा था। आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त प्रसाद सुर्वे ने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'अधिकारियों ने राजस्थान निवासी उत्तम सेन और भयंदर के रमेश पुरोहित को मौके से गिरफ्तार किया है। उनके पास से तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिनसे तस्करी रैकेट में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दोनों आरोपियों को पनवेल कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच में पता चला है कि यह किसी अंतरराज्यीय गिरोह का काम हो सकता है।' रविवार को, मादक पदार्थों की तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई में, मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र-3 के हवाई अड्डा आयुक्तालय के अधिकारियों ने अभियान के दौरान लगभग 14.73 करोड़ रुपये मूल्य की 14.738 किलोग्राम संदिग्ध एनडीपीएस हाइड्रोपोनिक खरपतवार (मारिजुआना) जब्त की। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि ये बरामदगी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई) पर की गई, जिसके परिणामस्वरूप एक यात्री को गिरफ्तार किया गया।

यात्री को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, 'विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई), मुंबई के सीमा शुल्क अधिकारियों ने उड़ान संख्या एमएच 194 से बैंकॉक से आ रहे एक यात्री को रोका।' एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इससे पहले 29 और 30 जुलाई के बीच चलाए गए अभियान के दौरान, मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र-3 के हवाई अड्डा आयुक्तालय के अधिकारियों ने लगभग 8 करोड़ रुपये मूल्य का 8.012 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक खरपतवार (मारिजुआना) जब्त किया था। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई) पर चार मामलों में जब्ती की गई, जिसके परिणामस्वरूप चार यात्रियों को गिरफ्तार किया गया।

नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न; 60 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई : पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में एक 60 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी, जो पीड़िता का चाचा है, पर बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस मामले की विस्तृत जाँच चल रही है। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, उस व्यक्ति ने कथित तौर पर पीड़िता के साथ सोते समय बलात्कार किया। घटना के बाद, नाबालिग को शिव के लोकमान्य तिलक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज किया गया। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई की गई, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है। इंकट पैदा हो गया है। शिशु गहनता चिकित्सा इकाई (पीआईसीयू) में 24 घंटे के अंदर तीन बच्चों की मौत हो गई। इस घटना ने चिंता बढ़ा दी है, खासकर इसलिए क्योंकि पीआईसीयू में आमतौर पर रोजाना एक से ज्यादा कलाकार दर्ज नहीं होते। एक सात साल के बच्चे की मौत में तीन मृतकों से जुड़ी कई जटिलताओं को शामिल किया गया है, जिसमें से एक मौत की सूचना दी गई है, जो कि एक मौत की सूचना से संबंधित है। अन्य दो मृतक 11 साल के बच्चे थे। अस्पताल के दस्तावेज़ों के अनुसार, एक की मौत के कारण शॉक और अन्य जटिलताओं का कारण हुआ, जबकि दूसरे की मौत के कारण हार्ट-श्वसन के अनुसार डॉक्टरों और टेपेडिक के कारण हुई।

पूर्व सांसद एवं मंत्री जगदीश गुप्ता को शिवसेना (शिंदे गुट) ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

पश्चिम विदर्भ के विभागीय प्रभारी पद पर किया नियुक्त

अमरावती। शिवसेना (शिंदे गुट) ने अपने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व सांसद एवं मंत्री जगदीश गुप्ता को पश्चिम विदर्भ विभागीय प्रभारी संघटक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे के आदेशानुसार की गई है। पार्टी नेतृत्व ने उम्मीद जताई है कि जगदीश गुप्ता हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व आधारित विचारों और धर्मवीर आनंद दिघे की कार्यशैली को जन-जन तक पहुंचाएंगे तथा गुट के संगठन को और मजबूत करेंगे। शिवसेना (शिंदे गुट) का मानना है कि जगदीश गुप्ता अपने प्रशासनिक अनुभव, जनसंपर्क और सांगठनिक क्षमता के माध्यम से पश्चिम विदर्भ में पार्टी को नई दिशा देंगे और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी के विस्तार में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस नियुक्ति से उनके करीबी और विश्वासू गजानन परकाले और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है, और इसे आगामी राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए गुट की सांगठनिक दृष्टि से एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

वसई विरार के सड़कों को गड्ढों से मुक्त करने का कार्य अधर में...

विरार : वसई विरार के निवासियों को लंबे समय से गड्ढों से मुक्त सड़कों का वादा किया गया है, लेकिन मानसून के साथ ही यह सपना एक बार फिर टूटता नजर आ रहा है। शहर की सड़कें गहरे गड्ढों से भर गई हैं, जिससे नागरिकों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। इस समस्या से सबसे ज्यादा बाइक और रिक्शा चालक प्रभावित हैं। कई साल पहले, वसई विरार महानगरपालिका ने शहर की सड़कों को गड्ढा-मुक्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य मानसून के दौरान जलभराव और गड्ढों की समस्या को खत्म करना था। इस योजना के तहत, 18,739 मीटर लंबी और 508 मीटर चौड़ी 51 सड़कों को कंक्रीट से बनाने का प्रस्ताव था, जिसके लिए 208. करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बावजूद, इस परियोजना पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। महापालिका के निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना का काम अभी चल रहा है और जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि, नागरिकों के अनुसार, ये सिर्फ खाली वादे हैं और जमीन पर कोई काम होता नहीं दिख रहा है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए, नगर निगम ने 2025-26 के बजट में कंक्रीटिंग के काम के लिए अलग से 150 करोड़ का प्रावधान किया है। यह कदम गड्ढों की संख्या को कम करने और मरम्मत की लागत को बचाने के लिए उठाया गया है। लेकिन, जब तक काम शुरू नहीं होता, तब तक ये फंड भी फाइलों में ही दबे रहेगा। सड़कों की खराब हालत को लेकर नागरिकों में भारी नाराजगी है।

सोशल मीडिया पर जनप्रतिनिधियों की आलोचना हो रही है और कई विधायक, मंत्री और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने महापालिका को जल्द से जल्द गड्ढे भरने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, नागरिक मानते हैं कि जब तक स्थायी वित्तीय समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक गड्ढों से मुक्त सड़कों का सपना सिर्फ वादों तक ही सीमित रहेगा। प्रशासन का कहना है कि परियोजना के लिए राज्य सरकार से मंजूरी का इंतजार है।

ठाणे में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर बड़ी कार्रवाई...

7,000 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित

ठाणे : ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना अब सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रह गया है। ठाणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (ऊध) ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पिछले पांच वर्षों में गंभीर नियम उल्लंघन करने वाले करीब 7,000 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं। यह कदम उन लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है जो नशे में गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाते हैं या भारी वाहनों में तय सीमा से अधिक माल लादते हैं। बता दें कि उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रोहित काटकर के अनुसार, हर साल औसतन 1,200 से 1,500 चालकों पर यह सख्त कार्रवाई की जाती है। काटकर ने बताया कि जो चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं, गति सीमा का उल्लंघन करते हैं या ओवरलोडिंग करते हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाती है। पहले चालक को नोटिस भेजा जाता है और जांच में दोषी पाए जाने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिया जाता है। काटकर ने यह भी स्पष्ट किया कि ऊध का मुख्य उद्देश्य लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करना है, लेकिन नियमों को तोड़ने वालों को दंडित करना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए विभाग ने अब लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई को प्राथमिकता दी है।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमांगिनी पाटिल ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नशे की हालत में वाहन न चलाएं, मोबाइल फोन का प्रयोग गाड़ी चलाते समय न करें, हेलमेट पहनें और सीट बेल्ट बांधे। उन्होंने कहा कि ये आदतें केवल आपकी ही नहीं, बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा बन सकती हैं। नशे में ड्राइविंग या ट्रैफिक नियमों की अनदेखी सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि सामाजिक अपराध भी है। ठाणे ऊध की यह पहल सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीरता को दर्शाती है और नागरिकों को यह संदेश देती है कि नियमों की अनदेखी का अंजाम अब और गंभीर होगा। सुरक्षित ड्राइविंग केवल नियम पालन नहीं, बल्कि सामाजिक ज़िम्मेदारी भी है।

पुणे में क्या सुरक्षित है....तो कुछ भी नहीं?

मनपाआयुक्त नवलकिशोर के बंगले से झुमर, सजावटी सामान, एसी गायब

मुन्ना मुजावर

पुणेः पुणे महानगरपालिका आयुक्त का शिवाजीनगर इलाके में मॉडल कॉलोनी में चित्तरंजन वाटिका के पास डेढ़ एकड़ में फैला एक विशाल बंगला है। इस बंगले में 24 घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं और बंगले के आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इससे चप्पे-चप्पे पर नज़र रखी जाती है। इसके साथ ही, इस इलाके में कुछ विधायक और कारोबारी भी रहते हैं। इसी वजह से प्रशासन इस इलाके पर खास ध्यान देता है। इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद, महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम के बंगले से महंगे झूमर, सजावटी सामान, टीवी, एसी और अन्य बिजली के उपकरण गायब हो गए हैं। इस घटना से हड़कंप मच गया है।

पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम को महानगरपालिका आयुक्त का पदभार संभाले लगभग दो महीने हो चुके हैं। इससे पहले, डॉ. राजेंद्र भोसले महानगरपालिका आयुक्त थे और वे चित्तरंजन वाटिका स्थित बंगले में रहते थे। चूँकि उनके बाद नवल किशोर राम रहने वाले थे, इसलिए महानगरपालिका भवन, बिजली और सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने घर का निरीक्षण किया। उस समय पता चला कि घर से चार एसी, झूमर, ऐतिहासिक इमारतों की पेंटिंग और अन्य पेंटिंग, पुराने पीतल और कांसे के लैंप, दो बड़े एलईडी टीवी, कॉफी मेकर, वॉकी-टॉकी सेट, रिमोट बेल, चिमनी से लैस किचन टॉप, वाटर प्यूरीफायर और अन्य सामग्री गायब थी। इससे हड़कंप मच गया। अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ये सामान कहां गया। इस बीच, प्रशासन द्वारा कुछ आवश्यक वस्तुओं की तत्काल खरीद कर ली गई है। हालांकि, अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए 20 लाख रुपये की निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन मुद्दा यह है कि नगर निगम आयुक्त के बंगले में मौजूद सामान आखिर कहां गया, इस पर चर्चा शुरू हो गई है।

नगर आयुक्त नवल किशोर राम ने इस संबंध में कहा, इस बंगले की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग के पास है। इसलिए, यह देखना उनका काम है कि यहां की सामग्री कहां गई। इसलिए, इस संबंध में संबंधित अधिकारी से पूछताछ की जाएगी, उन्होंने कहा, सारी जानकारी सामने आ जाएगी।

पुणे में 'एसटी' स्टेशनों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुणे में एक टीम गठित की गई है... तत्काल कार्यान्वयन के निर्देश

मुन्ना मुजावर

पुणेः पुणे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम (एसटी) के स्टेशनों जैसे स्वर्गेट, शिवाजीनगर, पिंपरी-चिंचवड़, दापोड़ी, राजगुरुनगर, भोर आदि पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाएगी। निवारक उपायों के तहत, एसटी निगम की सुरक्षा समिति ने सुझाव दिया है कि इन स्टेशनों पर पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी कैमरे, अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड लगाए जाएँ और स्टेशनों के बाहर अनधिकृत फेरीवालों, विक्रेताओं और निजी यात्री वाहनों में सवार लोगों के स्टेशनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए।

स्वर्गेट 'एसटी' स्टेशन पर महिलाओं पर अत्याचार की घटना के बाद, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में निवारक उपाय लागू करने के निर्देश दिए थे। तदनुसार, निगम की सुरक्षा समिति की टीम सोमवार को पुणे पहुँची और शहर के स्वर्गेट, शिवाजीनगर, पिंपरी-चिंचवड़, तलेगांव दाभाड़े, मंचर स्टेशनों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया, जबकि मंगलवार को उन्होंने तलेगांव दाभाड़े, राजगुरुनगर, भीमाशंकर और भोर स्टेशनों का निरीक्षण किया।

सुरक्षा एवं सतर्कता समिति अधिकारी शंकर लाडे, लेखा अधिकारी रोहन गायधानी, सिविल इंजीनियर राम राशिनकर, संभागीय परिवहन प्रबंधक सचिन शिंदे और यांत्रिक इंजीनियर स्मिता कुलकर्णी उपस्थित थे। एसटी निगम ने स्पष्ट किया कि अगले दो-तीन दिनों में तालुकाओं के प्रमुख स्टेशनों का निरीक्षण किया जाएगा।.

टीम द्वारा दिए गए सुझाव

- दापोडी और शिवाजीनगर बस स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाएँ
- स्टेशनों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जाए
- स्टेशन क्षेत्र में अनधिकृत फेरीवालों और निजी यात्री वाहनों के प्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए

यवत के दंगों के लिए पडलकर और संग्राम जिम्मेदार! शरद पवार गुट ने लगाया आरोप

सभा में भड़काऊ बयान देने के बाद हिंसा ने पकड़ी तुल

मुन्ना मुजावर

शरद चंद्र पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पुणे के दौंड तालुका के यवत में हुए दंगों के लिए ज़िम्मेदार सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने इस संबंध में राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखा है, जिसमें भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर और सत्तारूढ़ राकांपा विधायक संग्राम जगताप का नाम लिया गया है।

पिछले हफ़्ते, यवत के दौंड में एक समुदाय के युवक ने 1 अगस्त की सुबह सोशल मीडिया पर एक विवादित स्टेटस पोस्ट किया। इस पोस्ट की जानकारी मिलते ही गाँव में तनाव पैदा हो गया। इसके बाद, दोनों समुदायों ने एक-दूसरे पर पथराव किया और कुछ दोपहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद यहाँ भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई। गौरतलब है कि इस दंगे से एक दिन पहले, विधायक गोपीचंद पडलकर और संग्राम जगताप की यहाँ एक बैठक हुई थी। यह घटना दो दिन बाद हुई। इस पृष्ठभूमि में, राकांपा के शरद पवार गुट ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर इस दंगे के लिए ज़िम्मेदार विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

शरद पवार के समूह ने अपने पत्र में क्या कहा?

पार्टी ने अपने पत्र में कहा है कि, यवत तालुका के दौंड में एक व्यक्ति द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अपमान करने के दो दिन बाद, 31 जुलाई को शाम 5 बजे, विधायक गोपीचंद पडलकर, विधायक संग्राम जगताप, जय वैष्णव किन्नर अखाड़ा प्रमुख हेमांगी सखी और कुछ अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिंदू जनाक्रोश मोर्चा निकालकर पुलिस की अनुमति के बिना यवत में एक सार्वजनिक बैठक की। उक्त बैठक के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा की गई थी। उस बैठक में, उपरोक्त विधायक और अन्य कार्यकर्ताओं ने बहुत भड़काऊ भाषण दिए जिससे धार्मिक दरार पैदा हुई। भाषण का उद्देश्य शांति स्थापित करना नहीं था। इसके विपरीत, एक सार्वजनिक अपील की गई कि कार्रवाई पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए। वास्तव में, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अपमान करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने और दंडित करने का अधिकार नहीं है।

हालांकि, विधायकों ने विधानसभा और विधान परिषद में ली गई शपथ का उल्लंघन किया और उपस्थित युवाओं की भावनाओं को भड़काने के लिए भड़काऊ बयान दिए। जिसके कारण अगले दिन, एक अगस्त को यवत में बड़ी हिंसा हुई। बड़े पैमाने पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई। इस कृत्य और घटना की स्थानीय पुलिस ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पुलिस को यवत में तीन-चार दिनों से चल रहे तनावपूर्ण माहौल की जानकारी थी। पुलिस के पास इसके तमाम सबूत हैं। दरअसल, यह स्पष्ट है कि उक्त बैठक से माहौल भड़काने की कोशिश की जा रही थी और जहां धार्मिक दरार पैदा की जा रही थी, वहीं स्थानीय पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर अप्रत्यक्ष रूप से अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया।

मकोका के करवाई में सजा काटने के बाद जेल से रिहा होने पर मारिजुआना की तस्करी; सराईत गिरफ्तार; 26 किलो मारिजुआना जब्त

मुन्ना मुजावर

पुणेः महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत सजा काटकर जेल से रिहा हुए एक सराय निवासी को मादक पदार्थ निरोधक दस्ते (एएनएस) ने गांजा तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। उसके पास से 5.36 लाख रुपये मूल्य का 26 किलोग्राम गांजा, एक मोटरसाइकिल और 21.16 लाख रुपये मूल्य का एक मोबाइल फोन सेट जब्त किया गया है। इस मामले में अनिल उर्फ अन्ना सुभाष राख (उम्र 46, निवासी कालेपदल, हडपसर) को गिरफ्तार किया गया है। राख के खिलाफ फुरसुंगी पुलिस स्टेशन में मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। राख एक सरायपाल है। 2014 में हडपसर इलाके में हुई एक हत्या के मामले में उसके खिलाफ मकोका की कार्रवाई की गई थी। इस मामले में उसे दोषी ठहराया गया था। सजा पूरी करने के बाद वह छह-सात महीने पहले जेल से रिहा हुआ था। एएनएस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रशांत अन्नाछात्रे ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद उसने गांजे की तस्करी शुरू कर दी थी। मादक पदार्थ निरोधक दस्ता फुरसुंगी इलाके में गश्त कर रहा था। उसी समय राख एक कार में कटराज-मंतरवाड़ी रोड पर आया था। जाँच दल को सूचना मिली कि उसके पास गांजा है। इसके बाद पुलिस टीम ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। कार से 26 किलो गांजा जब्त किया गया। यह पता लगाने के लिए जाँच जारी है कि राख किससे गांजा लाया था और किसे बेचने वाला था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पंकज देशमुख, उपायुक्त निखिल पिंगले के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक प्रशांत अन्नाछत्रे, सहायक निरीक्षक अनिल सुरवसे, प्रवीण उत्तेकर, विनायक साल्वे, विशाल दलवी, सचिन माल्वे, नागेश राख, संदीप शिर्के, सुहास डोंगरे, दत्ताराम जाधव, दयानंद तेलंगे-पाटिल और टीम ने यह कार्रवाई की। शहर में गांजे की बिक्री और तस्करी बढ़ गई है। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। गांजा दूसरे नशों के मुकाबले सस्ता है। इस वजह से गांजे की मांग बढ़ रही है। हॉस्टल और कॉलेज के युवा गांजे का सेवन करते हैं। नाबालिगों को गांजा पीते देखा गया है। गांजे की तस्करी और बिक्री की दर दूसरे नशों के मुकाबले ज़्यादा है।

फिल्म 'खालिद का शिवाजी' पर आपत्ति; किसने लगाया झूठा इतिहास दिखाने का आरोप?

मुन्ना मुजावर

पुणेः फिल्म 'खालिद का शिवाजी' का ट्रेलर हाल ही में सोशल मीडिया पर रिलीज़ हुआ। इसके बाद कई संगठनों ने फिल्म का विरोध किया। आरोप लगाया गया कि फिल्म के कई दृश्यों में इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। अब, पुणे स्थित श्री शिव शंभू विचार मंच ने भी इस पर आपत्ति जताई है। संगठन ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि फिल्म में ऐतिहासिक रूप से गलत और झूठे दावे किए गए हैं।

नवी पेठ स्थित पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के प्रदेश संयोजक सुधीर थोरात, अखिल भारतीय पंच रामनंदी निर्वाणी अखाड़ा के महंत सुधीर दास महाराज, लेखक और वक्ता सौरभ करडे और अन्य लोग शामिल हुए।

थोरात ने कहा, 'फिल्म 'खालिद का शिवाजी' में गलत ऐतिहासिक संदर्भ दिए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का 35 प्रतिशत हिस्सा मुस्लिम था, महाराज के 35 में से 11 अंगरक्षक मुस्लिम थे और महाराज ने रायगढ़ किले पर मस्जिद बनवाई थी, ऐसा गलत इतिहास फिल्म 'खालिद का शिवाजी' में दिखाया गया है। हमारा मानना है कि इन दावों को पुष्ट करने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। इसलिए, हम मांग करते हैं कि सरकार फिल्म के निर्माता और निर्देशकों द्वारा उक्त संदर्भ और सबूत दिए बिना इस फिल्म का किसी भी मीडिया पर प्रसारण न करे।' इस अवसर पर उन्होंने यह भी आरोप लगाया, 'अगर फिल्म के ट्रेलर में इतनी खामियाँ हैं, तो पूरी फिल्म समाज को वैचारिक रूप से गुमराह करेगी और नई पीढ़ियों के बीच इतिहास के बारे में गलतफहमियाँ पैदा करेगी। यह शिवाजी के हिंदू स्वराज्य के महापुरुषों के सच्चे योगदान और बलिदान का श्रेय किसी और को देने का एक विश्वासघाती प्रयास है।'

महंत सुधीर दास महाराज ने कहा, 'सरकार को ऐसी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हम इस फिल्म के खिलाफ अदालत में याचिका दायर करेंगे। रायगढ़ किला विश्व धरोहर स्थल के रूप में पंजीकृत है। यह फिल्म मीडिया और सोशल मीडिया पर उस जगह के बारे में एक बहुत ही गलत भ्रम फैलाने की एक सोची-समझी साजिश है। इसलिए इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए।'

वार्ड के लिए पदाधिकारियों की तलाश अब राज्य सरकार के दरवाजे पर है...!

मुन्ना मुजावर

पुणेः आगामी नगर निगम चुनावों के लिए वार्डों का गठन करते समय, भारतीय जनता पार्टी के शहर पदाधिकारियों और नेताओं ने महागठबंधन में सहयोगी शिवसेना (शिंदे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) के पदाधिकारियों के साथ कोई चर्चा नहीं की, और इससे दोनों दलों के शहर पदाधिकारियों में असंतोष फैल गया है। इस वार्ड संरचना को शहरी विकास विभाग को भेज दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि शिवसेना (शिंदे) पार्टी के शहर पदाधिकारियों ने अब शिवसेना (शिंदे) पार्टी के दृष्टिकोण से सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे मुंबई का रास्ता अपनाया है। जब नगर निगम वार्डों का गठन कर रहा था, तब भाजपा ने उन्हें विश्वास में लिए बिना आपसी वार्ड संरचना कर ली। अब इस योजना को अंतिम मंजूरी के लिए शहरी विकास विभाग को भेज दिया गया है, और यह योजना अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, शिवसेना के पदाधिकारी मुंबई पहुँचकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने की योजना बना रहे हैं। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि शिवसेना के पदाधिकारियों के वार्डों में कुछ बदलाव किए जाएँ ताकि

शिवसेना को फ़ायदा हो, क्योंकि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नगरीय विकास विभाग के प्रभारी हैं। नगर निगम में भाजपा के पदाधिकारी वार्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे। चर्चा है कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए वार्ड बनाए हैं। इस बीच, नगरीय विकास विभाग एकनाथ शिंदे के पास होने के कारण, शिवसेना के पदाधिकारियों ने वार्ड ढाँचे में संतुलन बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वहीं, भाजपा द्वारा उन्हें विश्वास में न लेने के कारण, अब राकांपा के पदाधिकारी नगरीय विकास मंत्री एकनाथ शिंदे से सीधे मिलने और वार्ड ढाँचे को कुछ हद तक राष्ट्रवादी (अजित पवार) पार्टी के उम्मीदवारों के लिए फ़ायदेमंद बनाने की योजना बना रहे हैं। अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि नगर निगम चुनाव में महागठबंधन में शामिल भाजपा, शिवसेना (शिंदे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार) मिलकर लड़ेंगे या अकेले। पिछले नगर निगम चुनाव में भाजपा ने नगर निगम में 100 का आंकड़ा छुआ था। इसके अलावा, चूँकि अब केंद्र और राज्य में भाजपा के सांसदों और विधायकों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए नगर निगम चुनाव में भी भाजपा अपने दम पर सत्ता में आ सकती है। इसलिए, शहर भाजपा के पदाधिकारी महागठबंधन के ज़रिए चुनाव लड़ने के बजाय अकेले लड़ने पर ज़ोर दे रहे हैं। अगर महागठबंधन के ज़रिए चुनाव लड़ने का फ़ैसला होता है, तो सहयोगी दलों को सीटें देनी होंगी, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं के नाराज़ होने की आशंका के चलते भाजपा की ओर से वरिष्ठ नेताओं से माँग की जा रही है.

रिमोट के जरिए 19 लाख की बिजली चोरी; महावितरण ने रंगे हाथों पकड़ा; 77 हजार यूनिट का इस्तेमाल

पिंपरी-चिंचवड़ः महावितरण ने खुलासा किया है कि भोसरी एमआईडीसी में एक औद्योगिक ग्राहक पिछले 2 वर्षों से रिमोट कंट्रोल का उपयोग करके बिजली चोरी कर रहा था। महावितरण ने इस ग्राहक से 19 लाख 19 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है। बिजली चोरी में इस्तेमाल किए गए उपकरण जब्त कर लिए गए हैं।

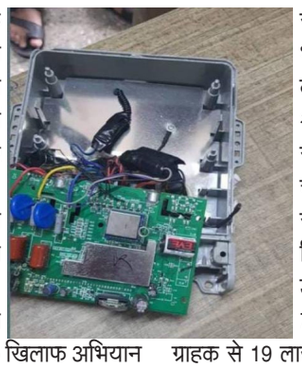

महावितरण के अध्यक्ष लोकेश चंद्र ने क्षेत्रीय अधिकारियों को बिजली वितरण घाटे को कम करने के निर्देश दिए थे। तदनुसार, महावितरण पुणे सर्कल के मुख्य अभियंता सुनील काकड़े ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए। गणेशखिंड सर्कल के अधीक्षण अभियंता सिंहजीराव गायकवाड़ और भोसरी डिवीजन के कार्यकारी अभियंता अतुल देवकर ने एक विशेष टीम बनाई। इंजीनियर गजानन झापे, बिजली कर्मचारी हर्षद लोखंडे, सोमनाथ गायकवाड़, महेश वाघमारे ने भोसरी एमआईडीसी में निरीक्षण शुरू किया। तब पता चला कि एक औद्योगिक ग्राहक, श्री गणेश प्रेसिंग के यहां रिमोट कंट्रोल से बिजली चोरी की जा रही थी। बिजली चोरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी सामग्रियों को महावितरण द्वारा जब्त कर लिया गया है। साथ ही, 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पिछले दो वर्षों में 77,270 यूनिट बिजली चोरी करने पर इस ग्राहक से 19 लाख 19 हजार 362 रुपये का जुर्माना और 2 लाख 30 हजार रुपये का समझौता भुगतान जुर्माना वसूला गया है। महावितरण की इस कार्रवाई से बिजली चोरों के

यह दैनिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक - मोहम्मद सईद अकबर अली शेख द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, युनिट नं. 4- ग्राऊंड फ्लोर, एन के. इंडस्ट्रियल इस्टेट, ऑफ आरे रोड, नीयर प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गेट नं. 2, गोरेगांव पूर्व, मुंबई 400 063 से छपवाकर, रूम नं. ३६१, जाकिर अली चॉल, स्कॉटर कॉलोनी, जोगेश्वरी (पूर्व),मुंबई ४०० ०६० से प्रकाशित. संपादक - मोहम्मद सईद अकबर अली शेख मो.: ९९३००२६९४२ / ९९३००२६९४३
कार्यकारी संपादक - विक्रम सेन email -fightagainstcriminal2016@gmail.com RNI. No. : MAHHIN/2016/71734 सभी पद अवैतनिक है, (विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मुंबई होगा)